में उर्वरक शेयर की क्षेत्रवार प्रतिशतता नीचे दी गई है:-

उर्वरक पोषकों का उत्पादन

(लाख टनों में)

वर्ष	विश्व	भारत	सार्वजनिक	भारत में क्षेत्र सहकारी	वार प्रतिशत शेयर निजी
1996-97	1481.74	111.55	30.09	18.63	51.28
1997-98	उपलब्ध नही है	130.61	31.15	21.35	47.50

S (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2001 से 2002) के लिये उर्वरक संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि नौवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2001-2002 के दौरान 140.27 लाख टन नाइट्रोजन तथा 33.33 लाख टन फास्फेट का उत्पादन किया जायेगा।

(ग) और (घ) उर्वरक उपयोग ने उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित रणनीति अपनाई है:

(i) मौजूदा उर्वरक संयंत्रो का विस्तार/रेट्रोफिटिंग पुनरुद्धार।

(ii) नेफथा पर आधारित विस्तार परियोजनाओं की स्थापना करके तथा मौजूदा संयंत्रो और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में दोहरी ईधन/फीडस्टाक सुविधाओं की स्थापना करके प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में कठिनाईयों पर काबू पाना, तथा

(iii) प्रचुर तथा सस्ते कच्चे माल के स्रोतों वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करना।

देश में यूरिया उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध है :-

(i) सामान्यतः उर्वरक उद्योग की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नही है।

(ii) नये संयंत्रों की स्थापना करने/मौजूदा संयंत्रो का आधुनिकीकरण करने के लिए पूंजीगत मालों के आयात पर नाममात्र का मौलिक सीमा शुल्क।

(iii) उर्वरक परियोजनाओं के पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को संभावित निर्यात लाभ बशर्ते ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली पद्धति के तहत की जाएं।

(iv) उर्वरक कच्चे मालों तथा मध्यवर्त्तियों के आयात पर नाममात्र का शुल्क।

(v) वर्तमान में यूरिया पर लागू प्रतिधारण मूल्य सह सब्सिडी स्कीम के तहत उद्यमियों को निवेश पर मुनासिब लाभ।

Re-orientation of Pharmaceutical Research Development

1862. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to take steps to reorient pharmaceutical research and development; and

(b) if so, what are the details of steps to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) and (b) As announced by the Union Finance Minister in his Budget speech of 27th February, 1999, a high level Committee is being set up in this Department to look into the pharmaceutical industry related R and D issues.